किए और अभ्रक के संसाधन की व्यवस्था करने हेतु धन खर्च किया और उन्होंने माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन को करोड़ों रुपये दिए लेकिन उक्त निगम ने 76.00 लाख रुपये का अपव्यय करने के बाद केवल 24.00 लाख रुपये ही आय दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करवाने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी): (क) संसाधित अभ्रक तथा अभ्रक स्क्रेप का निर्यात भारतीय अभ्रक व्यापार निगम (मिटका) के माध्यम से सरणीकृत है मिटका ने निगम द्वारा निर्धारित कीमतों के अनुसार मिटकों की ओर से सामान्य मुद्रा क्षेत्र से आर्डर प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व प्राइवेट अभ्रक निर्यातकों को मिटका के एजेंटों को बतौर कार्य करने की सुविधा प्रदान की है, तथापि प्राइवेट निर्यातकों को अपने ही स्रोतों से 50% आर्डरों की व्यवस्था करने के लिए अनुमति है। 1985-86 में संसाधित अभ्रक के कुल निर्यात 24.14 करोड़ रु. के हुए।

(ख) से (घ) 1985-86 के दौरान निर्यात के लिए कुल आर्डरों में से 69% आर्डर मिटका द्वारा स्वयं प्राप्त किए गए तथा 31% आर्डर प्राइवेट निर्यातकों द्वारा लाए गए वर्ष 1985-86 के दौरान प्राइवेट निर्यातकों द्वारा व्यवस्थित बैंक-टू-बैंक संविदा के संघ प्रभारों से 18.60 लाख रु. की आय हुई। किसी भी प्रकार की जांच करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इस संबंध में कंपनी के लेखाओं की संबंधित कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा की जाती है।

भारतीय अभ्रक व्यापार निगम

2782. **श्री कैलाश पति मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अभ्रक व्यापार निगम की स्थापना 1972 में की गई थी ताकि वह 2000 छोटे डीलरों से संसाधित अभ्रक निर्यात के लिए खरीदने को सुनिश्चित करे जिससे इन डीलरों और उनके साथ काम कर रहे श्रमिकों का जीवन-यापन होता रहे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारतीय अभ्रक व्यापार निगम माफिया गैंग को, जिसमें लगभग 200-300 ऐसे डीलर शामिल हैं जिनके पास जाली लाइसेंस हैं और जो सारे लाभों को हड़प रहे हैं; सहायता देता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी): (क) से (ग) अभ्रक व्यापार के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों के संरक्षण तथा विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से आरंभ में 24 जनवरी, 1972 से संसाधित अभ्रक का निर्यात भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम लि. की मार्फत सरणीकृत किया गया। बाद में 18 जून, 1974 को अभ्रक व्यापार निगम (मिटका) की स्थापना की गई और उसने इन कार्यों को अपने अधिकार में लिया। निर्यात आर्डरों की व्यवस्था करने के लिए मिटका वैध लाइसेंस धारक पंजीकृत व्यापारियों से, जो अपने माल की निविदा देने में स्वतंत्र हैं, माल प्राप्त करता है । संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी अभ्रक व्यापारी लाइसेंसों के आधार पर मिटका व्यापारियों का पंजीकरण करता है। निर्यात के लिए माल प्राप्त करते समय छोटे व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाती है।

Banking facilities enjoyed by Thapar Group from Oriental Bank of Commerce

2783. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Oriental Bank of Commerce was owned and con trolled by Thapar group prior to its nationalisation;

(b) what are the banking facilities being enjoyed by the Thapar Group from this Bank at present; and

(c) whether the borrowings of Thapar Group from this Bank are adequately secured as per the norms of the banking sector or any exceptions are made ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Prior to its nationalisation, the majority share-holding